



भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1980/असदिया 7, 1902
No. 275] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1980/ASADIA 7, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अ.स. संजालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1980

का. आ. 472(अ).—केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि खाद्य पदार्थों सम्बन्धी उद्योग में लगे भारतीय खाद्य निगम को, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा प्रदान किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस. -11017/6/80-डी. 1 ए.]

कू. म. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1980

S.O. 474(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Food Corporation of India engaged in the foodstuffs industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the Food Corporation of India to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/6/80-D.I.A.]

(Miss) M. SETH, Jt. Secy.